Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 12-08-2005

Participants : Suman Shri Ramji Lal

>

Title : Regarding proposed meeting of hon'ble Prime Minister with Superitendents of Police of all the States on 1 Septemeber, 2005.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, प्रशासनिक मशीनरी को सुधारने के नाम पर अभी प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश के जिलाधिकारियों का सम्मेलन किया था। अब एक सितम्बर को प्रधान मंत्री जी समूचे देश के 350 से अधिक पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन दिल्ली में कर रहे हैं। उसका जो एजैंडा तैयार हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि प्रशासनिक ढांचे की कछुआ चाल एवं प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त

---

* Not Recorded.

बनाने की दिशा में पहल करने का प्रयास है यह सम्मेलन। साथ ही साथ देश में बढ़ते हुए नक्सलवाद और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश कैसे लगे, यह विचार भी इस सम्मेलन में होना है।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। राज्यों की सरकार और देश की सरकार के बीच शक्तियों, कामों का बंटवारा है। संघीय ढांचे में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की जवाबदेही राज्य सरकार के प्रति है, भारत सरकार के प्रति नहीं है। यह संघीय व्यवस्था पर हमला है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का सम्मेलन, चाहे वह पुलिस अधीक्षक का सम्मेलन हो, चाहे जिलाधिकारियों का सम्मेलन हो, किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। नक्सलवाद और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है तो भारत सरकार मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाए, विचार-विमर्श करे, नीतियां bÉxÉÉA[R68]। क्योंकि राज्य सरकार जो नीतियां बनायेगी, जो कार्यक्रम तय करेगी, उसी को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यान्वित करेंगे। यह बहुत ही गलत परम्परा है।

मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि संघीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। राज्य सरकार और भारत सरकार के काम का अलग-अलग बंटवारा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जवाबदारी राज्य सरकार के प्रति है। मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्ति करना चाहता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि संघीय व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आवश्यक है कि भारत सरकार कोई ऐसा हस्तक्षेप न करे जिससे राज्यों की स्वायत्ता पर हमला हो। यह किसी भी कीमत पर उचित नहीं है।